आजकल

सेंसर बोर्ड का राजनीतिकरण

■ सिद्धार्थ शंकर गौतम

लीला सैम्सन ने भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड से इस्तीफा क्या दिया, इस संस्था से जुड़े पुराने विवादों और राजनीतिक गठजोड़ों का खुलना शुरू हो गया है। लीला सैमसन के समर्थन में सेंसर बोर्ड के 12 अन्य सदस्यों के इस्तीफे के बाद तो स्थिति विकट हो गई है। इस्तीफा देने वाले बोर्ड सदस्यों ने साफ तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कई मजबूरियां गिनाई हैं...

किसी जमाने में प्रियंका गांधी की नृत्य शिक्षिका रहीं लीला सैम्सन ने भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड से इस्तीफा क्या दिया, इस संस्था से जुड़े पुराने विवादों और राजनीतिक गठजोड़ों का खुलना शुरू हो गया है। लीला सैम्सन के समर्थन में सेंसर बोर्ड के 12 अन्य सदस्यों के इस्तीफे के बाद तो स्थिति अधिक विकट हो चुकी है। इस्तीफा देने वाले बोर्ड सदस्यों ने साफ तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कई मजबूरियां गिनाई हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप का यह कोई पहला मामला नहीं है, किंतु इस पूरे विवाद की जड़ में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम इंसान की फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड' को लेकर भाजपा के समर्थन की खबरें यह साबित करती हैं कि बोर्ड का कामकाज राजनीतिक तौर-तरीकों से मुक्ति नहीं पा सका है। सर्व-विदित है कि केंद्र में जिस दल की सरकार होती है, वह सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों में अपने लोगों की नियुक्ति का प्रयास करती है और यह परिपाटी नई तो कतई नहीं है।

वर्ष 2011 में जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने लीला सैम्सन को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था, तब उनकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ गई थी। कला की दुनिया की मशहूर शख्सियत लीला सैम्सन का फिल्मों की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। वह एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर और लेखक हैं। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से साल भर पहले लीला संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष बनाई गई थीं। वह साउथ जोन कल्चरल सेंटर की पदेन प्रमुख भी हैं। इसके अलावा वह चेन्नई में कलाक्षेत्र की डायरेक्टर भी हैं। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने खुले दिल से यह स्वीकार किया था कि वह कभी-कभार फिल्में देखती हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत को संप्रग सरकार ने सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था, जिसकी फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं थी। हो सकता है, प्रियंका की नृत्य शिक्षिका होने का उन्हें फायदा मिला हो, मगर योग्यता को परे रख क्या नियुक्तियां करना सरकार की अपनों को उपकृत करने की परिपाटी नहीं है?

ऐसा नहीं है कि लीला सैम्सन कला के क्षेत्र का कोई छोटा-मोटा नाम हो। लीला सैम्सन ने दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र और गंधर्व महाविद्यालय में भरतनाट्यम सिखाया है। सैम्सन को भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1990 में पद्मश्री और 1999-2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी

मिल चुका है, किंतु उनकी यह योग्यता सेंसर बोर्ड में तब सवालों के घेरे में आ जाती है जब पिछले साल चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनी फिल्म रंग रसिया को सेंसर बोर्ड बिना आपत्ति के पास कर देता है, जबकि इस फिल्म के एक सीन में तो अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री नंदना सेन को पूरी तरह नग्न दिखाया गया है। इस बाबत बोर्ड का कहना था कि उसको इस नग्नता में आर्ट दिखाई दी है। लीला की तर्क-शक्ति तब भी विवाद पैदा करती है जब वह आमिर खान की फिल्म पीके को बिना काट-छांट के पास कर देती है, जबकि उसमें हिंदू धर्म की अनेक मान्यताओं का जमकर मजाक बनाया गया है। सेंसर बोर्ड को तब भी तकलीफ होती है जब फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज को सिर्फ इसलिए टाल दिया जाता है क्योंकि वह हिंदू गुरु राम रहीम की फिल्म है।

यदि अपीलीय न्यायाधिकरण सेंसर बोर्ड के फैसले से असहमति जताता है तो यह कानूनी प्रक्रिया है न कि बोर्ड की स्वायत्ता पर कुठाराघात

दरअसल, सेंसर बोर्ड में जिस तरह के लोगों की नियुक्तियां हुईं, फिल्मों को लेकर उनकी सोच का दायरा बेहद संकुचित रहा है। 1949 में आई बरसात को सेंसर बोर्ड ने ए (वयस्क) श्रेणी में डाल दिया था। कारण सिर्फ इतना था कि फिल्म के कुछ दृश्यों में नरगिस बिना दुपट्टा पहने नजर आ रही थीं। 1961 में आई गुरुदत्त की चौदहवीं का चांद के गाने के एक सीन में वहीदा रहमान के चेहरे को नजदीक से फिल्माया गया था। सेंसर बोर्ड की इसमें आपत्ति थी कि वहीदा की आंखें लाल नजर आने से वह उत्तेजित कर रही हैं। वहीं 1975 में आई फिल्म आंधी को भी सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। चर्चा थी कि फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी के जीवन को चित्रित करती है, लेकिन इसी फिल्म को 1977 में आई जनता सरकार के शासन में पास भी कर दिया गया। 2003 में सिख दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हवाएं को सेंसर बोर्ड ने पास तो कर दिया, लेकिन दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में इसे दिखाने की अनुमति नहीं दी, जबकि यहीं उन दंगों के सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं। यही सेंसर बोर्ड रागिनी एमएमएस-2 और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों को सिनेमाघरों तक पहुंचता रहा है, मगर सार्थक सिनेमा को लेकर उसकी सोच की धार हमेशा कुंद पड़ती रही है।

फिर जहां तक सेंसर बोर्ड से इस्तीफा देने वाले सदस्यों के आरोपों की बात है तो यह सर्वविदित है कि संप्रग सरकार के दौरान नियुक्त हुए इन सदस्यों की श्रद्धा निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार के प्रति है, लिहाजा मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर इनका आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में बोर्ड में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें सरकार तक पहुंची थीं और सरकार ने उन पर कड़ा रुख भी अख्तियार किया था, अतः यह मानने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार से बोर्ड सदस्यों की अदावत किसी ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी और यह मौका उन्हें बाबा राम रहीम के रूप में मिला भी। सेंसर बोर्ड की निष्क्रिय अध्यक्ष ने कभी भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार के सामने नहीं उठाया, किंतु अपने इस्तीफे में उन्होंने बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला सार्वजनिक किया। क्या यह बोर्ड की अध्यक्ष का दोहरा मापदंड नहीं है? लीला सैम्सन के आरोपों के बाबत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संप्रग ने ही सेंसर बोर्ड का गठन किया था और वे सदस्य ही अभी तक काम कर रहे थे। अगर कोई भ्रष्टाचार है तो इसके लिए सदस्य खुद जिम्मेदार हैं। अरुण जेटली ने कहा कि यह आरोप कि सेंसर बोर्ड की बैठकें नहीं हुईं, खुद पर आरोप लगाने जैसा है। इन बैठकों का आयोजन सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष करता है मंत्री या सचिव नहीं। अगर बैठकें नहीं हुईं तो इसके लिए अध्यक्ष की निष्क्रियता जिम्मेदार है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंसर बोर्ड के बहाने संप्रग सरकार से जुड़े लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को किसी न किसी बहाने विवादों में घेरे रखना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने वादे से पीछे हटे और कांग्रेस को पुनः मजबूत होने में मदद मिले। वैसे भी कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड का भरपूर राजनीतिकरण किया। उसने 2004 में सेंसर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अनुपम खेर को महज इस आधार पर हटा दिया कि उन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने नियुक्त किया था। कम से कम मोदी सरकार तो ऐसा कतई नहीं करना चाहती है। यहां तक कि मोदी सरकार ने एक प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त कर अपीलीय न्यायाधिकरण नामक संस्था की गरिमा को भी बहाल किया वरना तो कांग्रेस ने उसका भी राजनीतिकरण कर दिया था।

यदि अपीलीय न्यायाधिकरण सेंसर बोर्ड के फैसले से असहमति जताता है तो यह कानूनी प्रक्रिया है न कि बोर्ड की स्वायत्ता पर कुठाराघात। क्या कोई अधीनस्थ संस्था उच्च संस्था के फैसले पर उंगली उठा सकती है? लीला सैम्सन ने एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की भांति सरकार को घेरने का प्रयास किया था, किंतु अपनी कला का प्रदर्शन करने में वह यहां चूक गईं और अब खुद उन पर और उनके अन्य साथियों पर अंगुलियां उठाई जा रही हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बाबा, सेंसर और सियासत

■ जावेद अनीस

धर्म, राजनीति और पैसे की तिकड़ी का खेल बड़ी तेजी से फलफूल रहा है। वैसे तो एक निराश, शोषित, परेशान और बिखरे समाज में बाबाओं का उभार कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब ये बाबा लोग बेलगाम हो जाते हैं और कुछ तो अपने आपको ईश्वर समझकर हर मामले में छूट पाना चाहते है और कानून व्यवस्था को भी अपना बंधक बनाने से गुरेज नहीं करते, पिछले चंद सालों की ही बात करें तो इस मामले में आशाराम, रामपाल, कृपालु महाराज, निर्मल बाबा जैसे बाबाओं ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। सियासत को भी बाबा लोग खासे पसंद आते हैं और हों भी क्यों ना आखिर ये लोग एकमुश्त वोट बैंक उपलब्ध कराने की कुव्वत जो रखते हैं। लोकतंत्र में बाबा लोग सत्ता का और सत्ता बाबाओं का बखूबी इस्तेमाल कर रही है।

चर्चित बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मामला उनकी विवादित फिल्म 'द मैसेंजर ऑफ गॉड' (एमएसजी) से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म को सरकारी मंजूरी मिलने के विरोध में पहले सेंसर बोर्ड प्रमुख लीला सैम्सन और बाद में आठ सदस्यों ने बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया है। लीला सैम्सन का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा सरकार की बढ़ती दखलअंदाजी के चलते दिया था।

दरअसल सभी बोर्ड सदस्यों ने एमएसजी देखकर इसे रिलीज के लिए मंजूर न करने का फैसला किया था। इसके बावजूद दो लोगों के ट्राइब्यूनल द्वारा इस फिल्म को मात्र 24 घंटे में हरी झंडी दे दी गई, जबकि आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने का समय लगता है।

वैसे, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। नई सरकार द्वार नए बोर्ड और अध्यक्ष नियुक्त करने तक इन्हें काम करते रहने को कहा गया था। गौरतलब है कि लीला सैम्सन ने अपना इस्तीफा देते हुए यह आरोप भी लगाया है कि एक अतिरिक्त प्रभार वाले सीईओ के जरिये मंत्रालय द्वारा सीबीएफसी के कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इस पर सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा सबूत की मांग करना पूरे प्रकरण से सरकार का दामन बचाने का प्रयास ज्यादा लगता है। सरकार का यह बचाव इसलिए भी नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि एक साथ पूरे सेंसर बोर्ड का इस्तीफा बहुत मायने रखता है और इस पूरे प्रकरण से प्रतीत होता है कि कहीं न कही पुरानी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों पर नई सरकार का दबाव था।

बताया जा रहा है कि इस फिल्म में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को भगवान बताया है। सेंसर बोर्ड का भी कहना था कि फिल्म विज्ञापन ज्यादा लग रही है। इसे अंध विश्वास को बढ़ावा देने वाला बताया था और यह भी पाया था कि फिल्म में दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य और संवाद हैं। पंजाब सरकार ने पहले ही इस आधार पर इस फिल्म पर रोक लगा दी थी कि इससे धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है। बाबा राम रहीम हरियाणा और पंजाब की राजनीति में क्या मुकाम रखते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उनसे समर्थन मांगने पहुंचे थे और चुनाव जीतने के बाद करीब 40 भाजपा विधायक बाबा की चौखट पर शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे डेरा सच्चा सौदा का भी बड़ा रोल रहा है। डेरा सच्चा सौदा की एक राजनीतिक इकाई भी है जो यह तय करने का काम करती है कि चुनाव के दौरान किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना है।

इस पूरे विवाद के मूल में सेंसर बोर्ड की पूर्ण स्वायत्तता है। वैसे कहने को तो सेंसर बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और उसे उसी तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ऐसा वास्तविक रूप से हो पाया हो। यह मामला सिर्फ सेंसर बोर्ड तक सीमित नहीं है इसी तरह के दूसरे तथाकथित स्वायत्त संस्थानों/आयोगों में भी यही अनुभव सामने आ रहे है। इनकी स्वायत्तता में सबसे बड़ा रोड़ा इनमें राजनीतिक नियुक्ति को लेकर ही सामने आता है। दूसरी तरफ नई सरकार की कार्यशैली ऐसी है जिसमें स्वायत्तता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मंत्रालयों तक में सारे फैसले पीएम ऑफिस के 'निर्देश' के अनुसार किए जा रहे हैं। 'द मैसेंजर ऑफ गॉड' के मामले में भी यही रवैया देखने में आया है जहां ट्रिब्यूनल द्वारा आनन-फानन में इस फिल्म को दिखाने की अनुमति दे दी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राज्यनामा : बिहार

एकता से पहले विवाद

जनता दल यू के भीतर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के रह रह कर आने वाले विवादास्पद बयान और अधिकारियों के तबादले से नीतीश खेमे की शांति भंग होती रहती है। जनता परिवार एका की कवायद के बीच जीतन राम मांझी की विदाई की खबरें और इनका खंडन भी आता रहा है। जदयू में जारी खींचतान के बीच भाजपा नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह कहकर विवाद को और हवा दे दी कि जदयू के 50 विधायक उनके संपर्क में हैं। तत्काल काउंटर हुआ, तो सरकार गिरा क्यों नहीं देते। जदयू के भीतर चल रहे खेल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर जदयू कार्यकर्ताओं के लिए दो दिनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, संगठन से जुड़े अन्य जुटे। चर्चा भाजपा से मुकाबले और इसके तौर तरीके पर केंद्रित रही। शिविर के अंतिम दिन नीतीश खेमे के मंत्री श्याम रजक के यहां भोज में बड़ी संख्या में मंत्रियों के जुटान ने विवाद को और हवा दे दी। दरअसल इसमें मुख्यमंत्री मांझी खेमे के लोग नहीं दिखे। और मांझी के करीबी कुछ मंत्रियों को तो आमंत्रण तक नहीं था। बहरहाल नीतीश के शिविर से संकेत गया कि संगठन पर उनका कब्जा बरकरार है और भोज से संदेश निकला कि मंत्रियों में भी नीतीश का पूरा प्रभाव है। 27 जनवरी को सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह ने भोज का आयोजन किया है। वह भी नीतीश खेमे के ही माने जाते हैं। बहरहाल राजद और जदयू के विलय का समय करीब आने के साथ जदयू में अंदरूनी दीवारें और गहरी होती जा रही हैं। एक तरफ दूसरे दल के साथ एका होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही दल में इस तरह फूट पड़ी हुई है। इसका जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।

गरीबों के लिए

मांझी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए नई योजना शुरू की है। शहरों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को मकान के लिए इंदिरा आवास की ही तर्ज पर राशि दी जाएगी। पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित होगा। इस तरह के मकान की लागत करीब तीन लाख रुपये है। प्रारंभिक चरण में पांच जिलों में करीब दस हजार आवास बनाए जाने हैं। कार्यान्वयन के लिए स्थानीय शहरी निकायों को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इसी सप्ताह राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मूलतः राजीव आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए इस तरह के मकान बनने हैं। लाभार्थी अपनी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से अपना आवास बना सकेंगे। जिन जिलों में यह योजना प्रभावी होगी उनमें पटना के साथ ही गया, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया शामिल हैं।

प्रधान का तोहफा

वोटों को एकजुट रखने के अभियान के तहत राजद-जदयू के विलय की कवायद के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार को पैकेज का तोहफा दिया है। बरौनी रिफाइनरी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आए धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार को 25 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का बुके पकड़ाया। बरौनी रिफाइनरी की क्षमता में डेढ़ गुना वृद्धि, बेगूसराय में पेट्रो केमिकल कांप्लेक्स की स्थापना, गोपालगंज और गया में बॉटलिंग प्लांट आदि पर यह राशि खर्च की जाएगी। बिहार को विशेष राज्य के पैकेज की मांग कर रहे नेताओं का मुंह भी इसी बहाने बंद करने की कोशिश की गई है। देखना है यह कोशिश कितनी कामयाब होती है।

पुलिस की लापरवाही

विधि-व्यवस्था को लेकर भाजपा मांझी सरकार पर लगातार हमले करती रही है। भाजपा नेता आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा के सरकार से अलग होने के बाद कानून-व्यवस्था बदतर हुई है। मुजफ्फरपुर के सरैया में इश्क के चक्कर में एक युवक की हत्या। और प्रतिक्रिया में गांव में आग लगाकर तीन दर्जन से अधिक घरों को स्वाहा कर दिया गया। पांच लोग मारे गए। इस घटना ने मांझी सरकार को परेशान कर दिया है। हालांकि डीएम, इंस्पेक्टर सहित चार पुलिस वाले इस मामले में नप गए हैं। इस प्रकरण में भी पुलिस की लापरवाही सामने आई। इश्क के मामले में अपहरण की शिकायत पर पुलिस ने शुरू में ही थोड़ी दिलचस्पी दिखाई होती तो पूरे मामले को टाला जा सकता था। पुलिस के लचर रवैये से लोगों में रोष है।

कर्पूरी के बहाने

बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। वोटों की गोलबंदी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में भारी पराजय और वोटों के आंकड़े को देखते हुए राजद-जदयू विलय के सहारे वोटों का बिखराव रोकने में जुटे हैं। मूल ध्यान पिछड़े वोटों को एकजुट रखने को लेकर है। भाजपा भी इसमें पैठ बनाने में जुटी है। अमूमन जातीय सम्मेलन न करने वाली भाजपा भी इस रास्ते चल पड़ी है। कर्पूरी जयंती समारोह को इसी कड़ी में पिछड़ों के बीच पैठ बनाने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के सुपर स्टार अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था। उनके भाषण में बिहार में सुशासन लाने का संदेश था तो निशाने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव रहे।

ग्लोबल वार्मिंग की आंच

मुद्दा

■ डॉ. भारत भूषण

दुनिया के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। इन वैज्ञानिकों का आकलन है कि अगर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को यहीं थामा न गया तो जल्द ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी। एक अरब से भी ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर होगा। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया में पड़ेगा। यह पहला मौका है जब वैज्ञानिकों ने इतने साफ शब्दों में जलवायु परिवर्तन के खतरे को व्यक्त किया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए वैश्विक गोलबंदी का भी प्रयास किया है ताकि उनकी चेतावनी का कोई असर हो। दुनियाभर के एक हजार से ज्यादा वैज्ञानिक संगठन एक हुए हैं। लंदन में शुरू किए गए अपने एक साझा अभियान में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विश्व के नेता इस साल संयुक्त राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों में असमानता और जलवायु परिवर्तन पर अहम फैसले करने में विफल रहते हैं तो इसके भयंकर नतीजे भुगतने को तैयार रहें।

एक हजार से अधिक संगठनों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन 'एक्शन 2015' अभियान के तहत सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को लक्ष्य बनाया गया है। इसमें साल 2000 में तय सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की जगह एक नए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस अभियान के तहत दिसंबर में पेरिस में होने वाले सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जाएगी। भारत के लिए इस सबका खास महत्व इसलिए है कि यह पहले से ही दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोगों का ठिकाना है। यह तब है जबकि इस सूची में यह भी स्वीकार किया गया है कि 1990 से 2010 के बीच दक्षिणपूर्वी एशिया में गरीबी दर में गिरावट आई है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोषी वे देश हैं जो आज सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं। यूरोप के तथाकथित विकसित देश और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगिकीकरण करके दुनिया को इस हालत में पंहुचाया है, लेकिन आज ये सब देश मिलकर सबसे ज्यादा भारत और चीन को कोस रहे हैं क्योंकि इन्हीं के पदचिह्नों पर चलते हुए आज भारत और चीन भी अपना औद्योगिक विकास करने में लगे हुए हैं। विकसित देश दुनिया की तेजी से उभरती दो आर्थिक महाशक्तियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के राष्ट्रप्रमुखों की गैरमौजूदगी को लेकर अमेरिका और उसकी हां में हां मिलाने वाले कई देशों ने इन दो एशियाई देशों की प्रतिबद्धता को लेकर अंगुली उठाई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे नकार दिया था।

यदि विश्व के नेता असमानता और जलवायु परिवर्तन पर अहम फैसले करने में विफल रहते हैं तो इसके भयंकर नतीजे भुगतने को तैयार रहें

विश्व बैंक ने तब ग्लोबल वार्मिंग के असर पर जारी एक ताजा रिपोर्ट में कहा था कि तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के कारण दुनिया के कई इलाकों में फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है। भविष्य में यह और कम हो सकती है क्योंकि जल आपूर्ति में भारी संकट खड़ा हो सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में गरीबी मुक्ति के जो अभियान चल रहे हैं उन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों के साझा आकलन में भी वही बात दोहराई गई है। एक्शन-2015 की जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन विकास के समक्ष एक बड़ा खतरा है, जो यह गरीबी मिटाने और समृद्धि को जनता में बांटने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अगर मजबूत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरती के तापमान में डेढ़ से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर कहीं यह बढ़ोतरी इस आशंका से भी ज्यादा करीब 4 प्रतिशत हो गई तो?

नई चिंता तापमान में तय मानी जा रही बढ़ोतरी के बाद भी तापमान के बढ़ने की आशंका है। इस बात की पहले से आशंका है कि औसत तापमान में औद्योगीकरण के पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह बीते समय और मौजूदा समय में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। इस तापमान की बढ़ोतरी के चलते समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चक्रवातों के जल्दी-जल्दी आने का खतरा बढ़ेगा। किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में असली खतरा यह है कि औसत वैश्विक तापमान में इस शताब्दी के अंत तक चार डिग्री की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में इस स्थिति को बढ़े हुए खतरों और वैश्विक अस्थिरता वाला भयावह विश्व बताया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि गरीबी को खत्म करना, वैश्विक समृद्धि को बढ़ाना और वैश्विक असमानता को कम करना पहले ही मुश्किल है। तापमान में दो डिग्री की और बढ़ोतरी होने से यह और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार दो डिग्री की वृद्धि ब्राजील की सोयाबीन फसल का उत्पादन 70 प्रतिशत तक कम कर सकती है। पिघलते ग्लेशियर एंडीज के आसपास के शहरों के लिए खतरा बन सकते हैं और पश्चिमी तट पर रहने वाले समुदायों की मत्स्य आपूर्ति में भी कमी हो सकती है। दो डिग्री की तापमान वृद्धि से दुनिया में मक्का, गेहूं और अंगूर की फसलों के उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी आ सकती है। उत्तरी रूस में इसके कारण बर्फ से ढंके क्षेत्र में लगातार बर्फ पिघलेगी। इसके चलते नुकसानदायक मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जिससे गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा और 2030 तक गरीबी मिटाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी को वर्ष 2030 तक मिटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह तभी संभव हो सकता है, जब गर्मी बढ़ने की रफ्तार महज दो डिग्री तक सीमित रहे, जिस पर अब शक पैदा हो गया है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2014 में कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में गरीबी दर 1990 के 45 फीसद से घटकर 2010 में 14 फीसद रह गई है। फिर भी अभी इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गरीबी फैली हुई है। अभी भी यहां दुनिया के समस्त निर्धनतम लोगों में से अकेले 32.9 फीसद हिस्सा भारत में रहता है। यह अनुपात चीन, नाइजीरिया और बांग्लादेश के अनुपात से भी ज्यादा है। बाल मृत्यु दर भी भारत में सर्वाधिक है जो कि गरीबी और भुखमरी का नतीजा होता है।

साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित सहस्त्राब्दि सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने 2015 तक के लिए गरीबी, भूख, लैंगिक समानता, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों से संबंधित आठ लक्ष्य तय किए थे। जिनमें से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। भारत में इस लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने पिछले दिनों कहा था कि मानव विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार समावेशी तरीके से सभी का विकास करना चाहती है। हेपतुल्ला के मुताबिक 'प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया है कि सरकार खासतौर से गरीबों के लिए समुचित स्वच्छता, पेयजल, मातृत्व और शिशु देखभाल को शीर्ष प्राथमिकता दे।' रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वैश्विक विकास में भारत की भूमिका दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर सहस्राब्दि लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकते, जब तक उन्हें भारत में हासिल नहीं किया जाता।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

फिर से

देश सेवा में एफडीआइ

आजकल देश सेवा के काम में बहुत बरक्कत है। जिसे देखो वह देश सेवा की लाइन में लगा हुआ है। देश सेवा का काम जिसको मिल जाता है वह अपने आपको धन्य समझता है। जिसको नहीं मिलता वह उदास हो जाता है। बड़े-बड़े जुगाड़ लगते हैं। बहुत पैसा ठुकता है तब कहीं देश सेवा का टिकट मिलता है। टिकट मिलने से ही देश सेवा का काम नहीं मिलता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देश सेवा का टिकट तो मिल जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। सब पैसे डूब जाते हैं। आदमी कुछ दिन उदास रहता है, लेकिन फिर देश सेवा का अगला काम देखता है। बहुत पहले से लाइन में लग जाता है। कोशिश करता है कि इस बार जैसे ही देश सेवा का काम निकले वह उसे हासिल कर ले। देश की भरपूर सेवा करके अपना और परिवार का कल्याण करे। साथ में नाम भी रोशन हो।

देश सेवा के काम में कम्पटीशन बहुत तगड़ा है। आदमी पहुंच वाला हो, दबंग हो, लोकप्रिय हो, मेहनती हो, लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हों तभी उसको देश सेवा का काम मिल सकता है। ये सब गुण तो देश में बहुतों के पास होते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे जरूरी चीज है पैसा। अंधाधुंध पैसा चाहिए देश सेवा का काम हासिल करने के लिए। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा जैसा ही है देश सेवा का काम। ज्यादा पैसा बड़ा काम। एक बार देश सेवा का काम मिल जाने पर सब नुकसान पूरा हो जाता है। पैसा वसूल हो जाता है। नाम रोशन होता है।

पैसा बहुत लगता है इस देश सेवा के काम में। करोड़ों फुंक जाते हैं देखते-देखते। देश सेवा के काम के लिए इतना पैसा जुटाना बड़ी फिजूलखर्ची है। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय सोचने चाहिए। एक उपाय तो यह है कि देश सेवा के काम में एफडीआइ को मंजूरी दे दी जाए। आजकल जिधर देखो एफडीआइ का हल्ला है। फिर देश सेवा में एफडीआइ लाने में क्या हर्जा है भाई। देश सेवा के काम में एफडीआइ आने से एक फायदा तो यह होगा कि फिर विदेशी पूंजी का हल्ला नहीं मचेगा। दूसरे चुनाव में अपने देश की जो पूंजी फुंकती है वह बचेगी। विदेशी पूंजी से बैनर, पोस्टर बनेंगे तो देश के लोगों को और रोजगार मिलेगा। कुछ लोगों को शायद एतराज हो सकता है कि देश सेवा के काम में विदेशी पूंजी का दखल खतरनाक है। देश के लिए खतरा है। तो भैये हमारा कहना यह है कि अभी कौन विदेशी पूंजी कम गदर काटे है। अभी वह चोरी से आती है तो गड़बड़ करती है। एफडीआइ के रास्ते आएगी तो अपना घर समझकर आएगी। उसको देश की चिंता होगी और वह यहां मन लगाकर काम करेगी।

फुरसतिया ब्लॉग में अनूप शुक्ला